We require grants-in-aid to the extent of Rs. 9 crores, whereas for others the figures are as follows:

Nagaland		Rs. 39 crores
Manipur		Rs. 27 ,,
Assam	..	Rs. 73 ,,
Orissa	..	Rs. 103 ,,
Jammu & Kashmir	..	Rs. 66 ,,
Tripura	..	Rs. 25 ,,
Meghalay	..	Rs. 25 ,,
Himachal Pradesh	..	Rs. 45 ,,

The Central Government will not be doing any big favour if it gives grant-in-aid of Rs. 9 crores to Goa, because the export duty which is earned by this territory is Rs. 55 crores per year on iron ore alone and this does not include export duty on manganess ore, on cashewnuts and so many other things. This is a pressing demand of Goa, Daman and Diu. This Government claims to be committed to the welfare of the people, as its name indicates. But empty promises would take us nowhere. It is our demand that as early as possible full-fledged Statehood should be granted to our territory. The erstwhile Congress Government was inclined to grant Statehood in respect of small States. The House must be aware of this. A couple of years back the concept of working statehood was adopted on the basis of the Morarka Committee report. Before becoming Prime Minister Mr. Morarji Desai was reported to have made a statement that it would be better if India had 4 or 5 major States and that small States were against the interest of the country. I request him to clarify this point. Government should express its policy on this issue of small States. I want to know specifically as to what the policy of the Government is on the question of granting full-fledged statehood to the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

With these words I thank you for the time given to me to speak and I thank the hon. Members for the patience with which they have heard my speech. I hope that the points raised by me will be replied to by the Government while replying to the debate.

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : सभापति महोदय, देश की जिस जनता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने का मौका हमें दिया है, उस जनता का मैं सब से पहले अभिनन्दन करना चाहता हूं। आज की यह नई स्थिति और यह नई सरकार लाने में जो लोग जेलों में गये, जिन्होंने सरकार के दमन का मुकाबला किया, और जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उन सब को भी मैं याद करना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे आज इस सदन में खड़ा होने का मौका दिया, और वह भी दो प्रकार के प्रचार को निष्फल बना कर—एक तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने मेरे क्षेत्र में जा कर कहा कि जार्ज फर्नांडिस बाहर का आदमी है, मुजफ्फरपुर की जनता उसे क्यों वोट दे, और उस वक्त और आज के भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे क्षेत्र में जा कर कहा कि जार्ज फर्नांडिस ईसाई है उसे मुजफ्फरपुर की जनता क्यों वोट दे ? मुजफ्फरपुर की जनता ने इस प्रकार के प्रचार के बावजूद मुझे वोट दिया। मेरे उस क्षेत्र में जाने पर हर प्रकार की रोक लगी रही, मैं जेल में बन्द रहा। इस देश की राजनीति में और देश के सार्वजनिक जीवन में मेरी सारी उम्र बीत गई, 19 साल की उम्र में मैं समाजवादी आन्दोलन में आया और तब से ले कर आज तक इस देश की जनता के बीच में मेरा काम रहा। सरकार से मतभेद रहे। संघर्ष चलता रहा। लेकिन हम ने नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन इस देश में आएंगे कि मुझ जैसे आदमी को दोनों हाथों में बेड़ियां डाल कर जंजीरों से पुलिस की पट्टी पर बांध कर शहर की सड़कों पर चलाया जायगा। ये सारी चीजें हुई।

[श्री ज र्ज फर्नान्डिस]

मगर इन सारी चीजों के बावजूद मुजफ्फरपुर की जिस जनता ने मुझे इस सदन में भेजा दिया उस को भी मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते समय धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मैंने कांग्रेस जनों के कई भाषण सुने, कुछ पढ़े । जनता की समस्याओं पर अब इन्होंने रोना शुरू किया है । दाम बढ़ रहें हैं, बहुत परेशानी है । बेकारी बढ़ रही है, बहुत परेशानी है । कब से दाम बढ़ने लगे ? बेकारी के आंकड़े पिछले दस बारह वर्षों से सरकार ने अपनी स्टेटिस्टिक्स की किताबों में देना ही बन्द कर दिया क्यों कि इतनी तेजी से इन लोगों ने बेकारी बढ़ाने की योजनाएं देश में बना कर रख दीं । क्षेत्रीय विषमता की कुछ बातें यहां पर हम ने सुनी । पिछले तीस सालों में जिन नीतियों को इस कांग्रेसी सरकार ने यहां पर चलाया, सिर्फ क्षेत्रीय विषमताओं को बढ़ाने और गांवों को लूट कर दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों को शानदार बनाने के सिवाय और कौन सी नीतियां उन की रहीं ? आज लाखों लोग रो रहे हैं । आज उन लोगों की याद इन को आने लगी । बिहार के पिछड़े हुए इलाके के मरे हुए लोगों की, आसाम, उड़ीसा जैसे पिछड़े प्रदेशों की, पूर्वोत्तर हिन्दुस्तान के पहाड़ी इलाकों में मरने वालों की आज याद आने लगी । तीस सालों में कौन सी नीतियां चलायीं ?

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कि वे कुछ अन्तर्मुखी हो जायं । गलतियां की हों तो उन को समझ लें । अपने दल की स्थिति को सुधारें या न सुधारें यह उन का काम है । लेकिन पिछले 30 सालों की गलतियों के बाद जरूर कुछ अन्त-र्मुखी हो कर जनता ने जो जिम्मेदारी आज जनत सर ार पर डाली है, और जिस जिम्मेदारी को निभान इस सरकार का कर्तव्य है, उस जिम्मेदारी को निभाने में आप हमारी मदद करें । उस मदद की आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं । क्यों कि आज आप भी महसूस कर रहे हैं कि जो दाम बढ़ाने का सिलसिला आप ने चलाया, और बेकारी बढ़ाने का सिलसिला आप ने चलाया और तीस साल जो देश को बरबाद किया है उसे हम लोग नए ढंग से उठाएं और नये ढंग से देश का निर्माण करें यह जम्मेदारी इस सरकार पर आई है । इसलिए आप जरूर टीका करें, जहां भूल हो, लेकिन उस के अलावा कुछ सहयोग दें ताकि इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने के लिए हम लोग कुछ ठोस कदम उठा सकें ।

ये समयाएं बड़ी और गहरी हैं जिन को हल करने का काम आज हम लोगों के जिम्मे आया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में और विशेषकर पिछले 11 वर्षों में देश के लोगों को झूठी बातों पर जिन्दा रखने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। बातें कितनी झूठी रहीं ...

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : "झूठ" नहीं "असत्य" बोलिए । पलियामेन्ट में आप "झूठ" नहीं बोल सकते ।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप क्यों शब्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, असलियत पर चलें । लोगों के सामने गलत आंकड़े रखकर बताया गया कि देश विकसित हो रहा है । बताया गया कि पिछले 11 सालों में देश इतना विकसित हो गया हैं । मेरे मित्रों को याद होगा कि पिछले साल इसी समय फरवरी, मार्च के समय में सारे देश में आप लोग "डायनेमिक डिकेड" बना रहे थे । सरकारी आंकड़ों से हमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितने करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों ने बरबाद किया । इस "डायनेमिक डिकेड" पर । मैंने उस समय भूमिगत अवस्था में रहकर एक पर्चा

निकाला जिसमें यह कहा कि यह "डाइनैमिक डिकेड" नहीं है, यह "डकाडेंट डिकेड" रही है । आज मैं इसका सबूत आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि देश के लोगों को उससे अवगत कराना बहुत जरूरी है । मैं विशेषकर पिछले दस वर्षों की बात कहूंगा, पिछले 30 वर्षों की नहीं क्योंकि फिर समय की समस्या आ जायेगी । फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर भी हम रोशनी डालेंगे । पिछले दस सालों में श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो "डायनेमिक डिकेड" रहा वह कितना "डायनेमिक" था और कितना "डेकाडेन्ट" था--इसको मैं बताना चाहता हूं ।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तब रुपए की कीमत थी 54 पैसे । दस साल "डायनैमिक डिकेड" चलाने के बाद रुपए की कीमत रह गई 25 पैसे । यह आपके ही आंकड़े हैं, मेरे नहीं । इसी तरह से जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तब इस देश "बिलो पावर्टी लाइन," गरीबी की रेखा के नीचे जो जनता थी उसकी संख्या थी 24 करोड़ लेकिन दस साल तक "डायनेमिक डिकेड" चलाने के बाद उनकी संख्या हो गई 42 करोड़ । यानी "डायनेमिक डकेड" में उनकी संख्या 18 करोड़ बढ़ गई ।

इसी तरह से जहां तक रोटी का सवाल है, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तब इस देश के लोगों को औसतन रोज 50 ग्राम दाल खाने को मिलती थी । वैसे तो बहुत से लोग भूखे हैं, 10-20 ग्राम दाल भी रोज खाने वाले बहुत हैं लेकिन औसत 50 ग्राम का था । श्रीमती गांधी की डायनेमिक डिकेड के बाद 50 ग्राम दाल का औसत 42 ग्राम ही रह गया । इसी तरह से जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं तब औसतन एक व्यक्ति को कपड़ा साढ़े 15 मीटर मिलता था जोकि 10 साल की "डायनेमिक डिकेड" के बाद 13 मीटर ही रह गया । इसी तरह से औसतन साल में एक व्यक्ति को 840 ग्राम वनस्पति मिलता था जोकि दस साल "डायनेमिक डिकेड" के बाद 748 ग्राम ही रह गया । इसी तरह से चीनी हालांकि हर एक को नहीं मिलती थी लेकिन औसतन एक आदमी के पीछे सालाना 7 किलोग्राम पैदा होती थी जोकि दस साल की "डायनेमिक डिकेड" के बाद 6 किलो ही रह गई । यह चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करके रखा और बताया कि इस देश से उत्पादन बढ़ा रहे है जबकि एक आदमी के पीछे जितना होता था वह भी घट गया और गरीबी बढ़ गई । आपने गलत आंकड़ों को पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाया यही मेरे कहने का मतलब है ।

एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं । देश मे विकास की बुनियाद इस बात पर निर्भर होती है कि इस्पात का कितना उत्पादन हो रहा है । जब श्रीमती गांधी की "डाइनैमिक डिकेड" शुरू हुई, उस समय साल मे एक आदमी के पीछे इस्पात पैदा होता था-9.3 किलो, लेकिन 10 वर्ष के बाद वह घट कर 7.8 किलो रह गया ।

इन के जो एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्जेज के रजिस्टर है--उनका हिसाब देखिये-- "डाइनैमिक डिकेड" शुरू होते समय बेरोजगारों की रजिस्टर्ड संख्या थी-26 लाख, लेकिन 10 वर्ष के बाद वह संख्या हो गई-1 करोड़। ग्रेजुएट्स की संख्या इन के लाइव रजिस्टर्ज" पर "डाइनैमिक डिकेड" शुरू होने के समय थी--1 लाख 19 हजार, लेकिन 10 वर्ष में यह बढ़कर 6 लाख हो गई । मैट्रीकुलेट्स तथा उस से ऊपर और ग्रैजुएट्स से नीचे के लोगों की संख्या "डाइनैमिक डिकेट" शुरू होते समय थी--8 लाख, लेकिन 10 वर्ष समाप्त होते-होते वह हो गई--30 लाख । हिन्दुस्तान से निरक्षर लोगों की संख्या "डाइनैमिक डिकेड शुरू होते समय थी-- 36 करोड़ लेकिन "डिकेड" समाप्त होते-होते

[श्री जार्ज फर्नांडिस]

वह संख्या हो गई–42 करोड़ । आप देख लीजिये —कितनी तरक्की हुई है ।

लेकिन, सभापति महोदय, एक क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई । वह कौन सा क्षेत्र था, बतलाऊं ? 1966–67 मे मैं इस लोक सभा का सदस्य था और उधर बैठा करता था । उस समय एक लड़का था जो हिन्दुस्तान में मैट्रिक पास हुआ था, बेकार था, एप्रेन्टिस शिप कर के आया था । हिन्दुस्तान का "डाइनैमिक डिकेड" समाप्त होते-होते वह कई करोड़ के मारुति लि० कारखाने का मालिक बन गया । इस जाह पर "डाइनैमिक डिकेड" ने वास्तव मे काम किया । लेकिन बाकी क्षेत्रों मे देश ने तरक्की नहीं की, देश बरबाद हुआ । मैं सारे आंकड़े इस समय नहीं रखूंगा अगर आप की दिलचस्पी हो, तो आप के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह सब छपा हुआ है । इस को आप जरूर पढ़िये और जो गलतियां हुई है उन को सुधारने का काम कीजिये ।

अभी एक सदस्य ने कहा कि "झूठ" शब्द मत बोलिये, "असत्य बोलिये–मैं आप को इस का उदाहरण भी देता हूं । इस सदन मे इन्होंने एक दस्तावेज़ पेश किया था–"व्हाई एमरजेंन्सी ?" इस दस्तावेज़ के बारे मे पता नहीं, उधर बैठे हुए लोगों को कब शर्म लगेगी या नहीं, क्योंकि यदि इस दस्तावेज़ को लेकर बहस की जाय तो शायद महीनों यह बहस चल सकती है । मगर इस वक्त तो मैं सिर्फ एक आदमी के बारे मे बतलाना चाहता हूं – जिस के बारे मे इस दस्तावेज़ मे लिखा है–वह व्यक्ति है--श्री जयप्रकाश नारायण । जय प्रकाश नारायण जी के बारे मे इन के किसी नौकरशाह या आई० बी० या पुलिस विभाग के किसी व्यक्ति ने जो लिखा है–उस को थोड़ा पढ़ लीजिये और उस को पढ़ कर अगर आप को शर्म आती है तो ज्यादा कुछ न कर सकें तो कम से कम उस महात्मा से क्षमा याचना ही कीजिये, इतना जरूर कीजिये ।

श्री सुरत बहादुर शाह (खैरी) : वह तो सिर्फ हयादार कर सकते हैं, बेहया क्षमा नहीं मांग सकते हैं ।

श्री जार्ज फर्नांन्डिस : इस दस्तावेज़ में 20 महीनों मे देश को किस तरह से कहां तक पहुंचाने का काम किया है—सब कुछ झूठ के आधार पर लिखने की कोशिश की गई है । इसी किताब मे एक चैप्टर है–रेल मज़दूरों की हड़ताल के बारे मे लिखते हैं —

"The railway strike of May, 1974 was essentially part of the movement for national disruption."

सभापति महोदय, हम नहीं चाहते थे कि रेल हड़ताल हो । मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने रेल हड़ताल को चलाया । दुनिया भर के अखबारों मे प्रचार किया गया, लन्दन-टाइम्ज़ में हज़ारों पाउण्ड खर्च कर के लेख छपाया कि हमारी वजह से करोड़ों या अरबों रुपया देश का बरबाद हो गया । मैं हड़ताल नहीं चाहता था । हम ने कुछ मांगे भेजी थीं । उस दिन मैं सदन में था, जब रेल बजट पर बहस चल रही थी । भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री श्री कुरेशी हमारी मांगों के पत्र को उठा कर सदन में दिखाने लगे कि हम ये मांगे मांगते हैं । उसमें हमारी 6 मांगें थीं ।

हमारे हिसाब से 350 करोड़ रुपये की बात थी मगर शुरू से ही मैं ने कहा था

Every demand is negotiable.

हड़ताल शुरू होने तक के क्षण तक मैं जेल से चिट्ठियां भेजता रहा कि :

Every demand is negotiable.

भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी ने अभी चन्द दिन पहले एक बयान दिया है जिस में उन्होंने लिखा है :

"When the last general strike was declared, I happened to be at

Mussoorie and on hearing about the strike I immediately returned to Delhi to take up the matter and see if a settlement could be arrived at. The then Railway Minister, L. N. Mishra called on me, I advised him to continue negotiations with the Railwaymen's Federation and their six point charter of demands. It is great pity that Shri George Fernandes was brought to Delhi for the purpose of negotiations but soon after, in a most indiscreet manner, sent to Tihar Jail."

उपाध्यक्ष महोदय, हम से बातचीत हो रही थी 30 अप्रैल की रात के 9 बजे तक। रेल भवन में हम ने बातचीत की थी। 1 मई को वे बातचीत करना चाहते थे लेकिन 1 मई, मजदूरों का दिवस है और मुझे लखनऊ में रेल मजदूरों के बीच में भाषण करना था और इस का मैं ने वायदा किया हुआ था। मैं ने कहा था कि मैं 2 तारीख को सुबह जहाज से दिल्ली पहुंच जाऊंगा और सीधे 9 बजे रेल भवन में बातचीत करने के लिए आऊंगा। साढ़े तीन बजे इन्डियन एयरलाइन्स का हवाई जहाज उड़ने वाला था लेकिन साढ़े 8 बजे तक उस को उड़ने नहीं दिया ताकि हम जा न पाएं। दरअसल यह विचार कर रहे थे कि इन को यहीं पकड़ लें या वहां पकड़ें? लखनऊ में मजदूर रात 12 बजे तक मेरा इन्तजार करते रहे और वहीं बैठे रहे और मैंने रात को 12 बजे लखनऊ स्टेशन के सामने अपना भाषण किया और रात को 2 बजे रेलवे रिटायरिंग रूम में सो गया। ढाई बजे दरवाजा खटखटाया गया और वहां पर दिल्ली पुलिस मीसा के अन्दर मेरी गिरफ्तारी का वारेन्ट लिये थी। रेलवे प्लेटफार्म को और स्टेशन को सैंकड़ों नहीं, हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया था। मैंने उन से पूछा कि मुझे कहां लिये जा रहे हो, तो कोई जवाब नहीं दिया गया। लखनऊ हवाई अड्डे पर बोर्डर सेक्यूरिटी फोर्स का हवाई जहाज दिल्ली से मेरा डिटेंशन आर्डर लेकर उड़ा और उस में बैठा कर मुझे पालम हवाई अड्डे लाया गया और वहां से मुझे तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया। 2 तारीख को मुझे 9 बजे बातचीत करने के लिए कहा था और 5 बजे मुझे जेल भेज दिया और इस पर ये लोग कहते थे कि :

This was an attempted national disruption.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि :

This was an attempted national disruption but not by the Railwaymen, but the Government of Mrs. Gandhi. This was an attempted national disruption.

और सबूत चाहिए, तो मैं देता हूं। हमारी बात को छोड़ दीजिए। इन की साथी श्रीमती पार्वती कृष्णन दिखाई नहीं दे रही हैं मगर उन के महान नेता कामरेड श्री पद अमृत डागें, जोकि हमारे भी मित्र है, द्वारा लिखी गई इस किताब को कांग्रेसी जरूर खरीदें। यह ए० आई० टी० यू० सी० की पब्लिकेशन है। इस का नाम है "दि रेलवे स्ट्राइक"। डागें साहब ने इस में लिखा है :

"The Government of the country, ruling in the name of democracy, had unleashed its armed forces against unarmed peaceful workers to compel them to work. It looked like the naked dictatorship of Roman Emperors, letting loose their armed solidery against their slaves who refused to be mere slaves only to work under the whip-lash. For 20 days in May 1974, India saw peaceful bourgeois democracy, installed in power by the ballot box, forcing the railwaymen to give up their demands and their right to strike to get those demands. This bourgeois democracy which swears by truth, non-violence, peace and the poor and the fundamentals of the Constitution attacked even the families of the Railwaymen, further illustrates the truth that when the worker has sold his labour power to the employer, he sold himself